

**दिल्ली**  
अधिकतम तापमान 36 डिग्री  
न्यूनतम तापमान 27 डिग्री

**एनसीआर**  
अधिकतम तापमान 36 डिग्री  
न्यूनतम तापमान 26 डिग्री

मंगलवार 23 सितंबर 2025  
सूर्योदय प्रातः 06:10 बजे  
सूर्यास्त सांय 18:18 बजे

# एनसीआर टुडे

करंट न्यूज करंट व्यूज



केनरा बैंक Canara Bank

SCAN & PAY

UPI ID: 30001262700246@cnrb

BHIM UPI

Digitally signed by NCR Masala

## ncr MASALA

India's Premium Masala

9410855900 ncrmasala@gmail.com

get online www.ncrmasala.com

गर्म मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा व अन्य रसोई मसाले

**झारखंड में दो सड़क हादसों में पांच की मौत, 15 घायल**

वेवार्ता. रामगढ़ \*। झारखंड के रामगढ़ और गोड्डा जिलों में सोमवार को दो सड़क हादसों की मौत हो गई और 15 घायल भी हुए। पहला हादसा रामगढ़ के छत्र गांव में सुबह 10 बजे हुआ, जब एक यात्री बस की टुक से आमने-सामने टक्कर हो गई। इसमें दो लोगों की मौत हुई और 15 घायल हुए। गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया। दूसरा हादसा गोड्डा के शीलल गांव में हुआ, जहां एक कार पलटकर खाई में गिर गई। इसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।

**एनआईए ने लड़की की तस्करी में गिरफ्तार 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार**

वेवार्ता. कोलकाता \*। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कोलकाता और बनगांव में पांच स्थानों पर छापा मार कर नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी में संलिप्तता के लिए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आभिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल परिचय बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रहने वाले हैं। एनआईए के एक बयान में कहा गया है कि पीड़िता को रेजगार देने के बहाने अवैध रूप से भारत में तस्करी कर लाया गया था और उसका शोषण किया गया। तलाशी अभियान में भारतीय, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी मुद्रा के अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

**पोरबंदर के सुभाषनगर जेट्टी पर लंगर डाले जहाज में लगी आग**

वेवार्ता. पोरबंदर \*। पोरबंदर, 22 सितंबर (वेब वार्ता)। गुजरात के पोरबंदर में सुभाषनगर जेट्टी पर खड़े एक जहाज में अचानक आग लग गई। यह जहाज जामनगर की एचआरएम एंड संस कंपनी का है और इसमें चावल व चीनी लदी हुई थी। आग की सूचना मिलते ही हमकल के तीन वाहन मौके पर पहुंचे। लेकिन जहाज पर चावल का भारी मात्रा में भंडारण होने के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। हालात को देखते हुए जहाज को समुद्र के बीच में खींचकर ले जाया गया ताकि आग से जेट्टी और आसपास के इलाके को कोई नुकसान न हो। यह जहाज सोमालिया के बोसासो बंदरगाह के लिए रवाना होने वाला था।

**पुणे प्रोफेसर ने किया पुरस्कार पत्र में फर्जीवाड़ा, गिरफ्तार**

वेवार्ता. पुणे \*। पुणे के वाघोली स्थित एक कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह यादव को प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनगर पुरस्कार (अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार) हासिल करने का दावा करने के लिए फर्जी पत्र बनाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल) की शिकायत पर पता चला कि यादव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के हस्ताक्षर जाली किए थे। जांच में स्पष्ट हुआ कि 2025-26 के लिए कोई चयन हुआ ही नहीं। पुलिस ने यादव को 26 सितंबर तक रिमांड पर भेजा है।

**मराठा आरक्षण सुनवाई से अलग हुई खंडपीठ**

वेवार्ता. मुंबई \*। बोम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को मराठा आरक्षण के लिए कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के महापट्ट सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। ये याचिकाएं जस्टिस रवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। हालांकि, न्यायमूर्ति पाटिल ने कहा कि वह इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते, जिसके बाद पीठ ने बिना कोई कारण बताए याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

## विमान हादसा: जांच रिपोर्ट लीक करना दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना: SC

एनसीआर टुडे, नई दिल्ली \*  
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के चुनिंदा हिस्सा मीडिया में लीक किए पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसमें हादसे के लिए पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराने वाली कहानी को बल मिला।  
श्री अदालत ने जांच रिपोर्ट के टुकड़ों में प्रकाशन को गैर- जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 'इस बात पर जोर दिया कि जांच पूरी होने तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने 'विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर गौर किया और कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट की गलती की ओर इशारा करने वाले कुछ पहलू का टुकड़ों में प्रकाशन 'गैर-जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इसके चलते मीडिया में कहानी बन गई।  
श्री अदालत ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को नोटिस जारी कर अपना अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने कहा कि 'जांच पूरी होने तक इस तरह की



रिपोर्टों की पूरी गोपनीयता होनी चाहिए। इसमें पीड़ितों की निजता और गरिमा का भी मुद्दा शामिल है।  
इसलिए हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह आदेश तब दिया, जब याचिकाकर्ता 'सेप्टी मैटर्स फाउंडेशन की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट की एक पंक्ति, जिसमें दुर्घटना के लिए पायलटों को जिम्मेदार ठहराया गया था, ने दुनिया भर के मीडिया में एक कहानी गढ़ी।  
भूषण ने पीठ से कहा कि 'जब तक लोगों को दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चलता, वे खतरों में हैं क्योंकि तब तक कोई निवारक कदम नहीं उठाया जा सकता। दुर्घटना को 100 दिन से अधिक हो गए हैं

में स्पष्टीकरण मिल जाएगा। इस पर पीठ ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग तो समझ में आती है, लेकिन प्लाट डेटा रिकॉर्डर से जानकारी की मांग 'संदिग्ध है। पीठ ने आग्रह किया कि किसी विशेष जानकारी को जारी करने का प्रतिद्वंद्वी एयरलाइनों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। साथ ही सुझाव दिया कि ऐसी जानकारी समय से पहले जारी नहीं की जानी चाहिए।  
टुकड़ों में जानकारी न हो सार्वजनिक शीर्ष अदालत ने कहा है कि 'हमें जानकारी को टुकड़ों में जारी नहीं करना चाहिए और नियमित जांच के तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने तक पूरी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। तभी हम वास्तविक कारण बता सकते हैं।  
इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधीनवक्ता भूषण ने एक पॉडकास्ट का हवाला दिया, जिसमें घटना के सभी पहलुओं की जांच करने का दावा किया गया था, और कहा कि यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह पायलट की लापरवाही का मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों में कुछ चुनिंदा हिस्से का मीडिया रिपोर्टिंग ने वास्तव में पूरी तस्वीर को विकृत कर दिया है। ऐसे में इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से 12 जून को लंदन के लिए उड़ान भरने के चंद सेकेंड बाद की एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी।

## उपग्रहों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में तैनात होंगे 'बॉडीगार्ड'



एनसीआर टुडे, नई दिल्ली \*  
भारत अंतरिक्ष में उपग्रहों की सुरक्षा के लिए 'बॉडीगार्ड' उपग्रह बनाने की योजना बना रहा। मामले से जुड़े जानकारों ने ये दावा किया है। 'बॉडीगार्ड' उपग्रह अंतरिक्ष में अहम मिशन से जुड़े उपग्रहों को किसी भी हमले से बचाने में मदद करेंगे। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना है।  
जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एक ऐसा 'बॉडीगार्ड' उपग्रह बनाया जाए जो खतरों को भांप कर अंतरिक्ष में घूम रहे दूसरे उपग्रहों की रक्षा करने का काम करे। जानकारों का दावा है कि उपग्रह-सुरक्षा परियोजना मोदी सरकार की एक बड़ी योजना है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत उपग्रहों की सुरक्षा के लिए 50 सुरक्षा उपग्रहों को मजबूत बनाना है।  
भारत इस कार्यक्रम के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सैटेलाइट (एलआईडीआर) लॉन्च कर सकता है। ये अंतरिक्ष में मौजूद खतरों का तुरंत पता लगाएगा जिससे पृथ्वी पर उपग्रह के लिए एक पुरा का मिलेगा। तकनीक और रडार से वैज्ञानिक मिशन से जुड़े उपग्रह को सुरक्षित करने का इंतजाम कर सकते हैं। अंतरिक्ष में

## परमाणु निरस्त्रीकरण अब पुरानी कहानी: किम जोंग

वेवार्ता. प्योंगयांग \*  
उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने कहा है कि परमाणु निरस्त्रीकरण एक अधवारणा के रूप में अपना अर्थ खो चुका है और उनका देश अपने परमाणु हथियारों को 'कभी नहीं' त्यागेगा, लेकिन अगर अमेरिका 'परमाणु निरस्त्रीकरण के अपने मोह को छोड़ दे' तो वह उसके साथ 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' पर चर्चा के लिए तैयार है।  
उत्तर कोरिया की संवाद समिति केसीएनए के अनुसार, श्री उन ने चौदहवीं सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के तेरहवें सत्र के दूसरे दिन यह टिप्पणी की। यह सत्र 20 से 21 सितंबर तक मानसुदु असेंबली हॉल में आयोजित किया गया था। अपने संबोधन में श्री किम ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी 'अच्छी यादें' साझा कीं। साल 2018-19 में हुयी इन मुलाकातों में प्रतिबंधों में राहत के बदले परमाणु निरस्त्रीकरण के कदमों पर चर्चा करने के लिए तीन बार बात की गयी थी।  
यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति के इस साल श्री किम से मिलने की इच्छा व्यक्त करने के एक महीने से भी कम समय बाद आयी है। उन्होंने तब श्री किम के साथ अपने 'बेहद मैत्रीपूर्ण' संबंधों पर जोर दिया था।  
श्री किम ने दक्षिण कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया की संभावना को सिर से खारिज कर दिया और दोहराया कि उनका देश कभी भी दक्षिण कोरिया के साथ पुनर्मिलन की कोशिश नहीं करेगा। उत्तर कोरिया, अपने इस पड़ोसी देश को अमेरिका के अधीन एक 'औपनिवेशिक देश' बता चुका है।

## मोदी देश विदेश में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा: राधाकृष्णन



एनसीआर टुडे, नई दिल्ली \*  
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और विदेश में लाखों लोगों के लिए एक जीवंत प्रेरणा बताते हुए कहा कि वह अपने आचरण से लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करते हैं।  
श्री राधाकृष्णन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों वाले दो खंडों का विमोचन करने के बाद कहा कि ये दोनों खंड प्रधानमंत्री के राष्ट्र के प्रति योगदान, दृष्टिकोण और सपनों को समझने की दृष्टिकोण कोरिया के साथ पुनर्मिलन की कोशिश 'देश और विदेश में लाखों लोगों के लिए एक जीवंत प्रेरणा बताया, जो अपने आचरण से लोगों को अपना

## लागातार दूसरे दिन लुदके शेर बाजार, आईटी कंपनियों में बड़ी गिरावट



वेवार्ता. मुंबई \*  
अमेरिका द्वारा एच-1बी वीजा के शुल्क में बढ़ोतरी से सोमवार को धरेलु शेर बाजारों में शुरूआती कारोबार में बिकवाली हावी रही और आईटी तथा टेक कंपनियों में बड़ी गिरावट देखी गई। इंफोसिस, एचसीएल टेकनोलॉजीज और टीसीएस के शेयरों में दो से ढाई प्रतिशत के बीच गिरावट चल रही थी।  
बीएससी का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 475.16 अंक की गिरावट के साथ 82,151.07 अंक पर खुला। हालांकि बाद में इसकी गिरावट कुछ कम हुई और खबर लिखे जाते समय यह पिछले कारोबारी दिवस की तुलना में 154.95 अंक (0.15 प्रतिशत) नीचे 82,471.28 अंक पर था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 सूचकांक भी 88.95 अंक की गिरावट में 25,238.10 अंक पर खुला और खबर लिखे जाते समय 31.30 अंक यानी 0.12 प्रतिशत गिरकर 25,296 अंक पर था।  
आईटी के अलावा फार्मा, स्वास्थ्य, टिकाऊ उपभोगिता उत्पाद सेक्टरों में गिरावट देखी गयी। वहीं, बैंकिंग, ऑटो, धातु और एफएमसीजी सेक्टरों के शेयरों में लिवाली का जोर रहा।  
आईटी कंपनियों के अलावा एलएंडटी और एमस्टेल भी गिरावट में रहने वाली प्रमुख कंपनियों थे। वहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स, ट्रेट और इंटरनल के शेयरों में तेजी थी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने 21 सितंबर से एचबी वीजा के लिए 1,00,000 डॉलर का शुल्क लगा दिया है। हालांकि बाद में यह स्पष्टीकरण दिया गया कि यह शुल्क पुराने बीमाधारकों पर लागू नहीं होगा और सिर्फ नये वीजा के लिए आवेदन करते समय चुकाना पड़ेगा।

## मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को दी 5100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात



एनसीआर टुडे, नई दिल्ली \*  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के इटानगर में 5100 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण कर प्रदेशवासियों को नवरात्र का उपहार दिया। इसमें 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की दो जलविद्युत परियोजना और तवांग में एक अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र की आधारशिला रखी है।  
श्री मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अरुणाचल की यह भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ देशभक्ति के उफान की भी धरती है। जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग भी केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य और शांति का प्रतीक है।  
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से देश में नेकट जेनेरेशन वरतु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस

मौसम में जनता जनार्दन को यह डबल बोनस मिला है।  
उन्होंने कहा कि 2014 में जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, तभी मैंने कांग्रेस की सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान लिया था। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं बल्कि राष्ट्र सर्वप्रथम (नेशन फर्स्ट) की भावना है। हमारा एक ही मंत्र 'नागरिक देवो भवः' है।  
जबकि कांग्रेस का यह मानना था कि इस प्रदेश में कम लोग हैं, लोकसभा की सिर्फ दो ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। हमारे अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो सूर्य की किरण सबसे पहले आती हैं लेकिन दुर्भाग्य से यहां विकास की किरण आते-आते कई दशक लग गए।

## सर्पदंश से युवक की मौत

एनसीआर टुडे, अलीगढ़ \*। थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव शाहगढ़ में एक युवक की जहरीले सांप के काटने से उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। गांव शाहगढ़ निवासी राजेश कुमार का छोटा बेटा योगेश कुमार शनिवार की रात खेत से घर लौट रहा था तभी रास्ते में उसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया था। स्वजन उसे आनन-फानन में मेडिकल कालेज अलीगढ़ ले गए थे जहां उपचार के दौरान सोमवार की सुबह मेडिकल में मृत्यु हो गई। हादसे की जानकारी पर मुलायम सिंह यादव युथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव महेश बघेल, सुनील सिंह, अनोखेखाला, टुनटुन बाबा, अनिल कुमार, भोले, सत्यम, प्रशु, टिकू, सोनू, सतेन्द्र कुमार, मनीष जादौन आदि दर्जनों लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए और परिजनों को सांत्वना दी।

## जनसुनवाई को बेहतर बनाने हेतु रिसेविंग सिस्टम शुरू

एनसीआर टुडे, अलीगढ़ \*। एसएसपी द्वारा नवरात्रि के शुभारम्भ के अवसर पर जनसुनवाई को और बेहतर बनाने के लिये पुलिस कार्यालय में रिसेविंग सिस्टम शुरू किया गया। जिसमें जो भी शिकायतकर्ता पुलिस ऑफिस आ रहे हैं उनको गुलाबी रंग की रिसेविंग दी जा रही है एवं प्राप्त समस्त शिकायती प्रार्थना पत्र कम्प्यूटर पर स्कैन किये जा रहे हैं और सम्बन्धित को अग्रसारित किये जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों पर पहुंचने वाले शिकायतकर्ताओं के लिए भी अगले 07 दिवस में रिसेविंग सिस्टम शुरू कर दिया जायेगा। जनपदवासियों से अनुरोध है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 14.00 बजे के मध्य एसएसपी कार्यालय में उपस्थित होकर एसएसपी के समक्ष अपनी समस्या रख सकते हैं। एसएसपी द्वारा शीघ्र ही उनकी शिकायत का निश्चय सुनिश्चित कराया जायेगा।

## 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस

एनसीआर टुडे, अलीगढ़ \*। दसवें आयुर्वेद दिवस की तैयारियों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाघर में जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक यह दिवस धनेतरस को मनाया जाता था, किंतु तिथि बदलने से आयोजन में कठिनाई आती थी। वर्ष 2025 से आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा, जो दिन-रात के संतुलन का प्रतीक है और आयुर्वेद के सिद्धांतों से मेल खाता है। इस वर्ष की थीम "मोटोपे के लिए आयुर्वेद आहार" निर्धारित की गई है। साथ ही डिजिटल युग में आयुर्वेद, भ्रामक विज्ञापनों से बचाव, कैन्सर देखभाल में आयुर्वेद, छात्र-छात्राओं में जागरूकता, पशु स्वास्थ्य, महिलाओं हेतु आयुर्वेद और "सहिता से बंटवारा" जैसी उप-थीमों भी शामिल रहेंगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रातःकाल 08 बजे से सुभाष चौक से हैबीटेट सेंटर तक जागरूकता रैली, विद्यालयों में विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगिता, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में चर्चा, किसानों के माध्यम चर्चा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

## नवजात बच्चियों को बाटी मच्छरदानी

एनसीआर टुडे, अलीगढ़ \*। जिला प्रोबेशन अधिकारी अजित कुमार के निर्देशन के क्रम में सोमवार को महिला कल्याण विभाग द्वारा मोहन लाल गौतम जिला महिला चिकित्सालय में 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत कन्या जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया गया। सीएमएस डॉ. तैय्यब की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 11 नवजात बच्चियों को मच्छरदानी वितरित की गई और सभी को कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में संरक्षण अधिकारी हितेश कुमार, वन स्टॉप सेंटर मैनेजर सीमा अंब्वास, एचईडब्ल्यू से वर्षा रानी, जेडर स्पेशलिस्ट नीतू सारस्वत एवं वंदना शर्मा वन स्टॉप से मंजू पैरामेडिकल नर्स उपस्थित रहे।

## दिल्ली क्रिकेट हब ने आठ विकेट से जीता मैच

एनसीआर टुडे, गाजियाबाद \*। अल्फा क्रिकेट मैदान में चल रहे प्रदीप श्रीवास्तव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में सोमवार को दिल्ली क्रिकेट हब और टीएनएम अकादमी के बीच मैच खेला गया। मैच में दिल्ली क्रिकेट हब ने आठ विकेट से जीत हासिल की। टॉस जीतकर टीएनएम अकादमी ने बल्लेबाजी करते हुए 35.4 ओवर में 197 रन बनाकर ऑल आउट हो गईं। कप्तान अविजीत त्यागी ने 51 और तजिंद्र लुबाना ने 45 रन बनाए।

# गुरुग्राम सेक्टर-23 में पानी की मेन पाइपलाइन फटी

## कई सेक्टरों और कॉलोनियों में जल संकट गहराया

गुरुग्राम, एजेंसी। गुरुग्राम सेक्टर-23 में पानी की मुख्य पाइप लाइन फटने से सात इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। इनमें सेक्टर-21, 22, 23, 23ए के अलावा गांव डूंडाहेड़ा, कार्टरपुरी और मौलाहेड़ा शामिल हैं। लोगों को पानी के लिए टैंकर पर आश्रित होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से यह स्थिति बनी है। शनिवार दोपहर को सेक्टर-23 के बूस्टिंग स्टेशन पर पाइप लाइन फट गई। इससे बूस्टिंग स्टेशन पानी में डूब गया। जीएमडीए ने बसई जल शोधन संयंत्र से पानी की सप्लाई को बंद कर दिया। इससे पेयजल सप्लाई ठप हो गई।



## टैंकर मंगाने को मजबूर

पानी की आपूर्ति न होने के कारण कई घरों में लोगों ने टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर होना पड़ा। पीने के पानी को लेकर भी लोगों को दुकानों से पानी के बोतलें खरीदने को मजबूर होना पड़ा। यह पहली बार नहीं है कि सेक्टर में अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजय ढाका, मुख्य अभियंता, नगर निगम, गुरुग्राम, सेक्टर-23 में जहां पर पानी की पाइप लाइन टूटी है, इसकी मरम्मत का कार्य लगभग हो गया है। प्रभावित इलाकों पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

## गुरुग्राम को जाम से राहत देने की तैयारी, दिल्ली-जयपुर हाईवे के पास कहां बनेगा नया अंडरपास?



गुरुग्राम, एजेंसी। दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित शंकर चौक पर जाम से राहत दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए डीएलएफ प्रबंधन ने मोलसरी एवेन्यू रोड से हाईवे पर जयपुर से दिल्ली की तरफ दो लेन का अंडरपास तैयार करने का प्रस्ताव बनाया है। हरियाणा सरकार ने इस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) को भेजा है। सिरहौल बॉर्डर के समीप स्थित शंकर चौक एक व्यस्त चौराहा है। दिल्ली से जयपुर की तरफ कई रिहायशी और व्यावसायिक कॉलोनियां हैं। हजारों की संख्या में दिल्ली से लोग इन कॉलोनियों में नौकरी के लिए आते हैं। शाम को वापसी जाते समय शंकर चौक के समीप से दिल्ली के लिए यू टर्न लेना पड़ता है। इस वजह से दिल्ली-जयपुर हाईवे पर डीएलएफ साइबर सिटी की तरफ मुड़ रहे वाहनों का आपस में मिलते हैं, जिस कारण जाम लगता है। डीएलएफ प्रबंधन ने एक प्रस्ताव बनाकर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को सौंपा है। इसके मुताबिक डीएलएफ मोलसरी एवेन्यू रोड पर दो लेन का अंडरपास दिल्ली-जयपुर हाईवे को क्रॉस करता हुआ दिल्ली की तरफ बना दिया जाए तो इससे शंकर चौक पर यू टर्न के कारण जाम नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव पर अधिकारियों की तरफ से विचार किया जा रहा है। इसे अभी मंजूरी नहीं मिल सकी है। डीएलएफ के एक अधिकारी के मुताबिक इस अंडरपास के निर्माण का खर्च डीएलएफ लिमिटेड उठाने को तैयार है।

गुरुग्राम, एजेंसी। दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित शंकर चौक पर जाम से राहत दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए डीएलएफ प्रबंधन ने मोलसरी एवेन्यू रोड से हाईवे पर जयपुर से दिल्ली की तरफ दो लेन का अंडरपास तैयार करने का प्रस्ताव बनाया है। हरियाणा सरकार ने इस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) को भेजा है। सिरहौल बॉर्डर के समीप स्थित शंकर चौक एक व्यस्त चौराहा है। दिल्ली से जयपुर की तरफ कई रिहायशी और व्यावसायिक कॉलोनियां हैं। हजारों की संख्या में दिल्ली से लोग इन कॉलोनियों में नौकरी के लिए आते हैं। शाम को वापसी जाते समय शंकर चौक के समीप से दिल्ली के लिए यू टर्न लेना पड़ता है। इस वजह से दिल्ली-जयपुर हाईवे पर डीएलएफ साइबर सिटी की तरफ मुड़ रहे वाहनों का आपस में मिलते हैं, जिस कारण जाम लगता है। डीएलएफ प्रबंधन ने एक प्रस्ताव बनाकर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) को सौंपा है। इसके मुताबिक डीएलएफ मोलसरी एवेन्यू रोड पर दो लेन का अंडरपास दिल्ली-जयपुर हाईवे को क्रॉस करता हुआ दिल्ली की तरफ बना दिया जाए तो इससे शंकर चौक पर यू टर्न के कारण जाम नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव पर अधिकारियों की तरफ से विचार किया जा रहा है। इसे अभी मंजूरी नहीं मिल सकी है। डीएलएफ के एक अधिकारी के मुताबिक इस अंडरपास के निर्माण का खर्च डीएलएफ लिमिटेड उठाने को तैयार है।

# ड्रोन कमांडो तैयार कर रही सेना, पहले बैच की ट्रेनिंग जारी

टेकनपुर, एजेंसी। मध्य प्रदेश के टेकनपुर में बीएसएफ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ड्रोन वॉरफेयर स्कूल शुरू हुआ है। पांच हफ्तों में 47 जवान यहां से ड्रोन कमांडो बनकर निकलेंगे।

यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की बीएसएफ की योजना का हिस्सा है। इस स्कूल में जवानों को ड्रोन उड़ाने, निगरानी करने, हमला करने और दुश्मन के ड्रॉन्स का मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएफ अकादमी के एडीजी शमशेर सिंह ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध ने दिखाया है कि आतंकवादी और बंदूकों से नहीं, बल्कि हवा में ड्रॉन्स से लड़ा जा रही है। वो चाहते हैं कि जवान ड्रोन को वैसा ही हथियार बनाएं जैसे वो इंसास राइफल को 15 सेकंड में खोलकर जोड़ लेते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में दो मुख्य कोर्स हैं- जवानों के लिए ड्रोन कमांडो और अप्सरों के लिए ड्रोन वॉरियर्स। स्कूल में तीन विंग हैं जो कि फ्लाईंग व पायलटिंग, रणनीति और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं। शमशेर सिंह ने बताया कि जवान ड्रोन को हथियार की तरह ले जा सकेंगे। वे इससे निगरानी, गश्त, दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने और जरूरत पड़ने पर बम गिराने का काम करेंगे।



डेवलपमेंट हैं। शमशेर सिंह ने बताया कि जवान ड्रोन को हथियार की तरह ले जा सकेंगे। वे इससे निगरानी, गश्त, दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने और जरूरत पड़ने पर बम गिराने का काम करेंगे।

## बनाए जा रहे खास तरह के ड्रोन

बीएसएफ ड्रोन को बड़े स्तर पर शामिल करने के लिए कई कदम उठा रही है। दिल्ली और कानपुर के आईआईटी के साथ मिलकर बीएसएफ अपने ड्रोन बना रही है, जिनमें हथियार, बम और हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे। टेकनपुर में रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ड्रोन टेक्नोलॉजी लैब बनाया गया है। यहां भारत-पाकिस्तान सीमा पर मार गिराए गए ड्रॉन्स से मिले डेटा और फॉरेंसिक्स पर काम किया जा रहा है। बीएसएफ का पुलिस टेक्नोलॉजी इन्वेषेशन सेंटर भी ड्रोन को हमलावर ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सीनियर बीएसएफ अप्सर ने बताया कि वो तेज गति वाले ड्रोन पर काम कर रहे हैं, जिनमें बंदूकें लगाई जा सकें। ऐसे ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो 500 किमी तक निगरानी कर सकें, काटेदार तारों तक की तस्वीरें ले सकें और 200 किलो तक वजन उठा सकें। ये सारी तकनीक सीमा पर गश्त व रक्षा को और मजबूत करेगी।

# फरीदाबाद के बाटा चौक पर बनेगा नमो भारत ट्रेन का इंटरचेंज



फरीदाबाद, एजेंसी। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में मेट्रो परियोजना के बाद जल्द नमो भारत परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की ओर से सर्वे का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। परियोजना के तहत बाटा चौक पर नमो भारत का इंटरचेंज बनेगा। यहां से नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। अगले सप्ताह इस पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। इसके बाद फरीदाबाद की एनसीआर में मजबूत कनेक्टिविटी होगी। शहर में कनेक्टिविटी के तौर सार्वजनिक परिवहन सेवा का काफी अभाव है।

गुरुग्राम जाने के लिए लोगों को अभी पहले दिल्ली के राजीव चौक या केंद्रीय सचिवालय जाना पड़ता है। वहां से दूसरे मेट्रो बदल कर गुरुग्राम और नोएडा पहुंचते हैं। ऐसे में आधे घंटे का समय तय करने में लोगों को दो से तीन घंटे लग जाते हैं। कैब से गुरुग्राम आवाजाही करना महिलाओं के लिए रात के अक्सर असुरक्षित होता है। दूसरी तरफ नोएडा के हवाई अड्डे के अगले माह से शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से फरीदाबाद की गुरुग्राम और नोएडा की बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी की गई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में मेट्रो के साथ बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के साथ इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। नमो भारत ट्रेन चलने से गुरुग्राम, मानेसर, धारुहेड़ा, भिवाड़ी और फरीदाबाद की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

# फरीदाबाद में टूटेंगी 100 दुकानें, रेलवे रोड चौड़ा करने को नगर निगम ने लगाए नोटिस



फरीदाबाद, एजेंसी। फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन रेलवे रोड को चौड़ा करने जा रहा है। इसके लिए रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई सौ दुकानों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ा जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने इन सभी दुकानों पर नोटिस लगा दिए हैं। इससे दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। गांधी कॉलोनी के सामने रेलवे रोड पर भगत सिंह चौक से लेकर ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास तक दुकानें बनी हुई हैं। ये दुकानें गांधी कॉलोनी में आती हैं। एनआईटी-पांच भगत सिंह चौक से लेकर थोड़ा आगे तक यह सड़क चार लेन है, लेकिन आगे चलकर यह सड़क संकरी है। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की इमारत नए सिरे से बनाई जा रही है। इस कारण अब रेलवे रोड को भी चौड़ा करने की तैयारी चल रही है। यह प्रक्रिया स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भी शुरू हुई थी, लेकिन तब कार्य नहीं हो पाया था।

# सेवाभवन में गंदगी टूटे फनीचर व गमलों को देख भड़के नगर आयुक्त

एनसीआर टुडे, अलीगढ़ \*। नगर निगम की सफाई व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले सेवा भवन कार्यालय की साफ सफाई को लेकर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने आज दोपहर बाद जनसुनवाई के उपरान्त अचानक निरीक्षण किया। नगर आयुक्त द्वितीय तल पर पहुंचे जहाँ निर्माण विभाग अपर नगर आयुक्त कार्यालय मुख्य अभियंता संपति विभाग नजारत और विधि विभाग के कई पटल स्थित हैं। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने विभिन्न कार्यालयों के बाहर की स्थिति का भीतिक सत्यापन किया। निरीक्षण में नगर आयुक्त को निर्माण विभाग में लिफ्ट के पास, मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर गंदगी, टूटे हुए फनीचर और सूखे गमले पड़े मिले। वहीं सीढ़ियों पर कई स्थानों पर पान और गुच्छे की पिक देखी गई जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस पर उन्होंने नजारत प्रभारी अधिकारी को 48 घंटे के भीतर विशेष अधिभान चलाकर सेवाभवन की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यालय में पान गुच्छा आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई कर्मचारी गुच्छा खाकर पिक करता पाया गया तो उसके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यालय की स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक कर्मचारी की है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एनसीआर टुडे, अलीगढ़ \*। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा नुमाइश मैदान की दुकानों में लगने वाले आतिशबाजी बाजार में प्रत्येक अस्थायी दुकानदार को जीएसटी पंजीयन अनिवार्य रूप से कराए जाने के विरोध में एक ज्ञापन एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर ग्रेड टू श्याम सुंदर तिवारी जी को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा के नेतृत्व में दिया गया। जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि अलीगढ़ में नुमाइश ग्राउंड की पक्की दुकानों में हर साल दीपावली पर आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाती हैं। जिससे शहर के लोग पटाखे खरीद कर अपना त्योहार मना सके पूर्व में बाजारों में छोटे-छोटे व्यापारी पटाखे की दुकान लगाकर आम जनता को त्योहार की सामग्री व आतिशबाजी उपलब्ध कराते थे जिससे आम जनता हर्षा-उल्लास से त्योहार मनाती थी परंतु अलीगढ़ में हुए हादसे के बाद अलीगढ़ प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर आतिशबाजी शहर के विभिन्न स्थानों पर बेचने की जगह नुमाइश ग्राउंड में आतिशबाजी बाजार लगाने का फैसला किया जिस शहर में कोई दुर्घटना ना हो सके। नुमाइश ग्राउंड में आतिशबाजी



नुमाइश ग्राउंड में आतिशबाजी बाजार लगाने का फैसला किया जिस शहर में कोई दुर्घटना ना हो सके। नुमाइश ग्राउंड में आतिशबाजी





## संपादकीय अमेरिका के लिए आत्मघाती होंगी ट्रम्प की नीतियां

अमेरिकी इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि एक राष्ट्रपति ऐसे बने थे, जो दुनिया बदल डालने, अपनी उंगली पर नचाने की हनक पाले हुए थे, परंतु खुद भी मजाक के पात्र बन गए थे। आज डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी इतिहास के सबसे हास्यापद राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, ट्रम्प सुबह पाकिस्तान के साथ होते हैं तो शाम को भारत के पक्ष में हो जाते हैं।

कभी चाइना के राष्ट्रपति की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं तो कभी रूसिया के राष्ट्रपति के सम्मान में नारे लगाने लगते हैं। कभी भारत को मित्र बताते हैं तो कभी भारत को सबसे बड़ा दुश्मन... समझ नहीं आता कि ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब से ट्रम्प दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, तब से ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने भारत के खिलाफ़ गलत बयानी न किया हो। पहले 50% टैरिफ लगा दिया, और अब एच-1 वीजा में सखी लगा दी है। ट्रम्प भली भांति जानते हैं कि दक्षिण एशिया में चीन की दादागिरी के सामने अगर कोई टिक सकता है तो वो केवल और केवल भारत है।

अन्यथा दक्षिणी एशिया में चाइना अमेरिका की ध्वजियाँ उड़ा देगा। ट्रम्प हर दिन भारतीय मीडिया में छाप रहे हैं। आजकल अपनी वीजा पॉलिसी के लिए खबरों में हैं। हर दिन ट्रम्प भारत के खिलाफ निर्णय लेते हैं जिससे भारत के बाज़ार में हलचल हो भारतीय लोगों को परेशानी का कारण पड़ता है। ट्रम्प को भूलना नहीं चाहिए कि भारत एक संप्रभुता वाला राष्ट्र है,

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एच-1बी वीजा के लिए आवेदन शुल्क को बढ़ाकर 100000 डॉलर यानी लगभग 84 लाख रुपये कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों की सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है, जिन्हें अब अपनी नौकरी पर खतरा नजर आ रहा है।

असमंजस की स्थिति और बढ़ गई जब अमेरिकी दिग्गज कंपनियों ने कर्मचारियों को 20 सितम्बर तक हर हाल में अमेरिका वापस लौटने की सलाह दी। इस बीच वॉल्ट हाउस ने बयान जारी कर स्थाित को साफ किया है। वॉल्ट हाउस की प्रम सेक्रेटरी कैरोलिन लोवेंट ने शांतिवार को स्पष्ट किया है कि हाल ही में घोषित 10000 डॉलर का एच-1बी वीजा शुल्क केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा। उन्होंने साफ कहा कि यह वार्षिक शुल्क नहीं है। दरअसल ट्रंप की एच-1बी वीजा में व्यापक बदलाव की योजना ने भारतीय आईटी पेशेवरों और कंपनियों में यह आशंका पैदा कर दी है कि अमेरिका से बाहर रहने वाले वीजा होल्डर को वापस लौटने के लिए तत्काल समय सीमा का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को लेकर भारत में जबरदस्त हलचल हो गई है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स एच-1बी वीजा प्रोग्राम के तहत अमेरिका में नौकरी करने जाते हैं। देखा जाए तो इस कदम से भारतीय परिवारों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। भारत सरकार ने उम्मीद जताई कि इन मुश्किलों को अमेरिकी अधिकारी सही ढंग से हल कर सकते हैं।

भारत और अमेरिका दोनों देशों के उद्योग जगत की इन्वोवेशन और क्रिएटिविटी में हिस्सेदारी है और उनसे आगे बढ़ने के बेहतरे रास्ते पर पारमर्श की उम्मीद की जा सकती है। स्कूल्ड लोगों का आजावाही ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, इन्वोवेशन, आर्थिक वृद्धि, प्रतिस्पर्धा और संपन्नता बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए, नीति-निर्माता हाल के अमेरिकी फैसले का आकलन आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच गहरे पीपल –टू पीपल संबंध भी शामिल हैं।

एक बड़ी चिंता यह खड़ी हो गई है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद क्या भारत में ऐसे लोग जो अमेरिका जाकर काम करने की खाहिश रखते हैं और अपना देस छोड़ते हैं, उनका यह सपना टूट जाएगा क्योंकि कंपनियां किसी कमचारी के लिए इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए शायद तैयार नहीं होंगी। यह फैसला 21 सितंबर से लागू होगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही होगा। दो लाख से ज्यादा भारतीयों पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी आईटी कंपनियों में काम करने वालों पर असर पड़ेगा। अब अमेरिका में कम नौकरियों के अवसर होंगे।

अमेरिकी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या पीएचडी करने वाले छात्रों पर असर पड़ेगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में सीमित अवसर होंगे, अगर आप पढ़ाई करने गए और वहां पर आप नौकरी का ऑफर तलाशते हैं तो वो भी सीमित हो जायेंगे क्योंकि वरीयता होगी अमेरिका के लोगों को लिया जाए। भारतीय छात्रों और लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा।

अमेरिका में करियर की शुरुआत करने वालों को दिक्कत होगी। अमेरिका में अधिकर भारतीय आईटी क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। यानी कि जो लोग जो आईटी प्रोफेशनल्स है या फिर दूसरे कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। मिड-लेवल और एंटी लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलने में मुश्किल आएगी।

अमेरिकी कंपनियां नौकरियां दूसरे देशों से आउटसोर्स कर सकती हैं। यानी अब जो दूसरे देश है वहां पर भी इसका उनको अवसर मिलेगा, यानि भारतीयों को भारिक के लोगों को इसका सीधा नुकसान हो रहा है। यह कदम केवल भारतीयों पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा, इसका सीधा असर अमेरिका में भी पड़ेगा, वहाँ की आर्थिक स्थिति पर असर होगा, परंतु ट्रम्पद ट्रम्प ने ठान लिया है कि अमेरिका को चाहे जितना नुकसान हो जाए, चर्चा में बने रहने के लिए अनाप – शनाप निर्णय लेते रहेंगे। इसलिए कहना गलत नहीं कि अमेरिकी इतिहास के सबसे अपरिपक्व राष्ट्रपति सिद्ध होंगे।

गजियाबाद, मंगलवार 23 सितंबर 2025

# ट्रंप ने टैरिफ के बाद वीजा शुल्क बढ़ाया : मोदी फेल

शकील अख्तर

भारत का युवा बोलेगा। आज नहीं तो कब बोलेगा कि उसे भी वैसी शिक्षा और फिर उसके बाद नौकरी के ऐसे अवसर क्यों नहीं मिल रहे? उसे पकौड़े बेचने की अपमानजनक सलाह क्यों दी जा रही है? आईआईटी से इंजीनियर बनने के बदले उसे आईटीआई से मेकेनिक क्यों बनाया जा रहा है?

जब नया नया सोशल मीडिया आया था तो लोग वहां हैप्पी बर्थ डे के मैसेज पाकर खुश हो जाते थे। केक फूल शैम्पेन की इमोजी देखकर खुद को मशहूर हरती समझने लगते थे। लेकिन अब सामान्य आदमी भी सच को समझ चुका है कि यह सारी मुबारकबादें ऐसी ही जिसे आज के युवा की भाषा में एवई कहते हैं, होती है। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेशों से जन्मदिन की बधाइयां पाकर अभी भी यह समझते हैं कि वे कोई बड़ाई बड़ी अन्तरराष्ट्रीय हरती हैं। विश्व गुरु जो वे कहते हैं उसका गुमान और बढ़ जाता है।

विदेश मंत्रालय में एक से एक काबिल अफसर हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह बता सके कि यह एक सामान्य औपचारिकता है। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी ऐसी ही बधाइयां मिलती हैं। और भारत तो एक बड़ा देश है इसलिए यहां के प्रधानमंत्रियों को मिलना स्वाभाविक है।

और यह तो कोई शिाओं में भी नहीं बता सकता कि जैसे सोशल मीडिया पर जो ज्यादा ध्यान आकर्षण चाहता है लिख देता है कि नहीं दोगे बधाइयां उसे फिर लोग दे ही देते हैं।

जन्मदिन की बधाइयां कोई पैमाना नहीं आपके महत्वपूर्ण होने का। मगर हमारे यहां जिस तरह से गोदी मीडिया ने खुशियां मनाई, भक्त एक-एक बधाई गिनकर शोर मचाने लगे कि देखो कितना मनाई है दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष हमारे मोदी जी को और फिर खुद मोदी जी ने एक एक राष्ट्राध्यक्ष को दिए धन्यवाद

# न्याय की रीढ़ पर वार : क्यों जरूरी है अधिवक्ता संरक्षण कानून

<b>पवन शुक्ला</b>
<span></span>
अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की माँग उत्तर प्रदेश में लगातार तेज हो रही है। हापुड़ से वाराणसी तक हुई घटनाओं ने वकीलों की असुरक्षा को उजागर किया है। विधि आयोग और बार काउंसिल अपनी सिफारिशें सरकार को दे चुके हैं। अब जरूरत है कि विधानमंडल तुरंत अधिनियम लागू कर न्यायापालिका की रीढ़ को मजबूती दे।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में वकील समाज का अधिन्न रहना है। अदालत की चौखट पर जब आम नागरिक न्याय की उम्मीद लेकर पहुँचता है, तो उसका सबसे बड़ा सहाय अधिवक्ता ही होता है। अधिवक्ता न केवल अपने मुवकिल का पक्ष रखते हैं, बल्कि न्यायापालिका और जनसाधारण के बीच एक सतह का तबू का कार्य करते हैं। किंतु दुखद है कि जो वर्ग कानून और व्यवस्था की रक्षा करता है, वही आज खुद असुरक्षित है। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की शुरुआत जुलाई 2021 में हुई, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका मसौदा प्रस्तुत किया। इसमें अधिवक्ताओं को हिंसा, धमकी और उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा के ठोस प्रावधान रखे गए। 2022 में संसद की स्थायी समिति ने मसौदे की समीक्षा कर संशोधनों की सिफारिश की। इसके बाद मार्च 2023 में राजस्थान पहला राज्य बना जिसने यह अधिनियम पारित कर अधिवक्ताओं को सुरक्षा का संकट दिया और अन्य राज्यों में भी उम्मीद जगाई।
उत्तर प्रदेश में यह माँग 29 अगस्त 2023 की हापुड़ घटना के बाद और तीव्र हो गई। उस

को जिस तरह प्रचारित किया गया वह ऐसा था जैसे इसके जरिए आप विश्व विजय की घोषणा कर रहे हों। खासतौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जन्मदिन की बधाई तो ऐसे बताई गई कि जैसे ट्रंप ने आत्म समर्पण कर दिया हो। जैसे राजा का जन्मदिन होता था तो खुश होकर कुछ दे या न दे मगर नाराज होने पर सजा जरूर देता था।

वैसे ही पेश किया गया कि ट्रंप समझ गया कि अगर मोदी जी नाराज हो गए तो फिर बस समझ लेना खैर नहीं। डर कर ट्रंप ने फोन किया। मगर दो दिन भी नहीं बीते और ट्रंप ने फिर बता दिया कि वह अपने लिए नए लगाने वाले मोदी को एक चुनाव प्रचार करने वाले से ज्यादा नहीं समझ रहा।

पचास प्रतिशत टैरिफ के बाद भारतीयों के लिए वीजा एच -1बी की फीस सौ गुना तक बढ़ा दी। एक लाख डॉलर। मतलब लगभग 90 लाख रूपए। और यह जब आप सुबह इन पंक्तियों को पढ़ रहे होंगे तो लागू हो चुका होगा। पहले इस वीजा के लिए छह लाख रूपए देना होता था। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा।

भक्त और अब उसी तरह का हो चुका मीडिया कई तर्क लेकर समाने आया है कि यह सब देशों को लिए है। वह यह नहीं बता सकता कि सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट भारत ने बनाए हैं। और 2014 से पहले। नेहरू द्वारा स्थापित आईटीआई ने। अभी विदेश में रह रहे एक डॉक्टर और लेखक प्रवीण झा ने बहुत अच्छा लिखा है कि एक अमेरिकी टीवी पत्रकार ने कहा कि 'हम सऊदी अरब से तेल मंगाते हैं, जापान से गाड़ियां, स्कार्लेटेंड से विस्की, लेकिन आपको मालूम है हम भारत से कौन सी बेशकीमती चीज मंगाते हैं? हम मंगाते हैं वहां के लोग। दुनिया के सबसे दिमागी और परिश्रमी इंजीनियर जो भारत से आते हैं।'

और यह सारे इंजीनियर नेहरू द्वारा स्थापित आईआईटी से निकले हैं। मोदी जी ने इनका मजाक उड़ाने में भी कोई कसर नहीं रखी कहा

# अधिवक्ताओं को सुरक्षित और पक्के चैंबर उपलब्ध कराने, सामूहिक बीमा योजना लागू करने और महामारी जैसी आपात परिस्थितियों में उन्हें न्यूनतम पंद्रह हजार रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने का सुझाव शामिल था।

आयोग ने यह भी कहा कि किसी अधिवक्ता की गिरफ्तारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न हो और गिरफ्तारी की स्थिति में 24 घंटे के भीतर संबंधित बार एसोसिएशन को सूचना दी जाए। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रारूप में अधिवक्ताओं पर हिंसा, धमकी, उत्पीड़न, संपत्ति का नुकसान और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना गया है।

दोषी पाए जाने पर छह महीने से पाँच वर्ष तक की सजा और पचास हजार से दस लाख रुपये तक का जुर्माना होगा, जबकि पुनरावृत्ति की स्थिति में यह सजा दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। अदालत को पीड़ित अधिवक्ता को मुआवजा देने का अधिकार होगा।

लेकिन अधिवक्ता समाज को अपेक्षित परिणाम अब तक नहीं मिले। प्रयाराज में अधिवक्ता अखिलेश शुक्ला की दिवंगदहई हत्या ने यह संदेश दिया कि पेशेवर दायित्व निभाने वाले वकील भी असुरक्षित हैं।

17 सितंबर 2025 को वाराणसी जिला न्यायालय परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच टकराव हुआ, जिसमें उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार गंभीर रूप से घायल हुए और लगभग 70 अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया।

इस घटना के बाद अधिवक्ताओं ने काम का बहिष्कार किया और अदालतों का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। 19 सितंबर

# संपादकीय

# अधिवक्ता संरक्षण कानून



आईआईटी नहीं आईटीआई चाहिए। वही खोल दिते! लेकिन केवल बातें! नेहरू को नीचा दिखाते के लिए उनकी हद बात का विरोध। मगर अब शायद चलेगा नहीं!

वीजा की यह नई फीस लाखों भारतीयों को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर देगी। बता दें कि इस वीजा प्रणाली के अन्तर्गत 75 प्रतिशत वीजा भारतीयों को मिलते थे। इसलिए गोदी मीडिया के इस बचाव में कोई दम नहीं है कि शुल्क पूरी दुनिया के लिए बढ़ाया गया है। जहां नेहरू, इन्दिरा गांधी जैसे नेता ही नहीं हुए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया है और खासतौर से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में जिससे वहां ऐसे आईटी, हेल्थ, फाइनेंस इंजीनियरिंग, विज्ञान जैसे क्षेत्रों के प्रोफेशनल निकलत पाए हों।

भारत का युवा बोलेगा। आज नहीं तो कब बोलेगा कि उसे भी वैसी शिक्षा और फिर उसके बाद नौकरी के ऐसे अवसर क्यों नहीं मिल रहे? उसे पकौड़े बेचने की अपमानजनक सलाह क्यों दी जा रही है? आईआईटी से इंजीनियर बनने के बदले उसे आईटीआई से मेकेनिक क्यों बनाया जा रहा है?

प्रधानमंत्रियों की लकीरें छोटी करना शुरू कर दीं। देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि अपनी ही पार्टी के वाजपेयी तक का नाम नहीं लेते। भाजपा में वाजपेयी से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ। भाजपा के पहले प्रधानमंत्री हैं।

मगर उनके नाम पर भी 11 साल में कुछ नहीं बनाया। न्यालियर जम्मू प्रदेश जहां के वे रहने वाले थे उनका मजम हुआ। चूने लिखे वहां भी उनके नाम पर कोई एक चीज नहीं बनाई गई। एचडी देवगौड़ा तो अभी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री उनके समर्थन में हैं।

मगर कभी उनकी तारीफ भी नहीं करते बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति को वापसी में देवगौड़ा का महत्वपूर्ण रोल था।

प्रसंगवार बता दें कि आतंकवादियों से हथियार डलवाने में और कश्मीर के युवकों को पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों से अलग करने में देवगौड़ा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वाजपेयी सरकार ने हरियत कान्फ्रेंस से पहली बार अधिकृत बातचीत की थी।

अभी पुरानी सरकारों पर जबर्दस्ती सवाल उठाने के लिए यासिन मलिक को ले आए। इसके पहले 2017 में राहुल ने मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री कहा था। विदेश नीति के साथ अमेरिका के इसी वीजा मामले में अमेरिका के सामने झुकने पर। कांग्रेस अध्यक्ष खरगो ने इस मामले में और साफ बोला है।

उन्होंने कहा कि मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं होती। सही है। पिछले 11 साल से मोदी जी केवल अपनी छवि चमका रहे हैं। जबकि इससे पहले यह होता था कि सरकार देश के हित के लिए काम करती थीं।

अपनी व्यक्तिगत छवि की चिन्ता किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। देश आगे बढ़ेगा, देश की जनता को फायदा होगा, युवा को रोजगार के अवसर मिलेंगे यही सब हर प्रधानमंत्री का उद्देश्य होता था।

यहां तो यह हुआ कि अपनी लकीर बड़ी करने के चक्कर में प्रधानमंत्री बाकी सब

# अधिवक्ता संरक्षण कानून

अधिनियम के त्वरित क्रियान्वयन की माँग की। आज स्थिति यह है कि बार काउंसिल और विधि आयोग दोनों अपनी रिपोर्ट और सुझाव सरकार को दे चुके हैं।

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कर उदाहरण प्रस्तुत कर चुका है, किंतु उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं को अब भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली है। “यदि अधिवक्ता सुरक्षित नहीं होंगे, तो न्यायापालिका की रीढ़ टूट जाएगी। यह केवल वकीलों का प्रश्न नहीं, लोकतंत्र की आत्मा का प्रश्न है।” —उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन शिव किशोर गौड़।

यहां मुद्दा केवल वकीलों की अभिरक्षा और सम्मानजनक वातावरण का नहीं है, बल्कि न्यायापालिका की आत्मा का है। अधिवक्ता वह दीपक हैं जो अंधेरे में न्याय की लौ जलाए रखते हैं और समाज को अन्याय के अंधकार से मार्गदर्शन देते हैं। यदि यह दीपक डगमगा जाए, तो न केवल अधिवक्ताओं का अस्तित्व संकट में पड़ेगा, बल्कि नागरिकों के न्याय पाने का अधिकार भी कमजोर पड़ जाएगा।

हापुड़ की लाठीचार्ज, प्रयागराज का खून, वाराणसी का टकराव और मुरादाबाद का अमानवीय हमला हमें यह चेतावनी दे रहे हैं कि अब देश की कोई गुंजाइश नहीं है। यह अधिनियम वकीलों के जीवन की दाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सांस है।

उत्तर प्रदेश की विधान सभा और विधान परिषद को इस पर अब और मौन नहीं रहना चाहिए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर न्याय की ज्योति को बचाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। यही समय है, यही अवसर है—यदि अभी नहीं तो शायद कभी नहीं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

# अनुत्तरित सवाल है सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ

प्रमोद भाग्य

संदर्भः असम में घुसपैठ और बदलती जनसांख्यिकी पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान अनुत्तरित सवालों को नए ढंग से राजनीतिक मुद्दों में बदलना प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी की विलक्षण पैली रही है। इस परिप्रेक्ष्य में जम्मू-कश्मीर को विशेषता दर्ज देने वाली धारा-370, 35-ए, तीन तलाक और राम मंदिर जैसे आजादी के बाद से अनुत्तरित चले आ रहे प्रश्नों के समाधान के बाद मोदी ने असम की भरती से घुसपैठ करने और कराने वालों को कड़ा संदेश दिया है।

उन्होंने दरांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों को मदद से जनसांख्यिकीय घनत्व बदलने की साजिश चल रही है, जो राश्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हमारी सरकार घुसपैठियों को देश के सामान-संसाधन पर कब्जा नहीं करने देगी।’

घुसपैठियों को मदद देने वालों को सीधी चुनौती देते हुए मोदी ने कहा, ‘घुसपैठियों को हटाने में हम अपना जीवन लगा देंगे। घुसपैठियों को पनाह देने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब इन्हें संरक्षण देती रही, जिससे घुसपैठिए हमेशा भारत में बस जाएं और भारत का राजनीतिक भविष्य तय करें। कांग्रेस के लिए देशहित से बड़ा, अपने वोट-बैंक का हित रहा है। किंतु अब यह नहीं चलेगा।’

बंगाल, असम और पूर्वांचल राज्यों में

स्थानीय बनाम विदेशी नागरिकों का मसला एक बड़ी समस्या बन गया है। जो यहां के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को लंबे समय से झकझोर रहा है। असम के लोगों की शिकायत है कि बांग्लादेश म्यांमार से बड़ी संख्या में घुसपैठ करके आए मुस्लिमों ने उनके न केवल आजीविका के संसाधनों को हथिया लिया है, बल्कि कृषि भूमि पर भी काबिज हो गए हैं।

इस कारण राज्य का जनसंख्यात्मक घनत्व बिगड़ रहा है। लिहाजा वहां के मूल की निवासी बोडो आदिवासी और घुसपैठियों के बीच जानलेवा हिंसक झड़पें भी होती रहती हैं। नतीजन अवैध और स्थाई नागरिकों की पहचान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता पत्रक बनाने की पहल हुई।

इस निर्देश के मुताबिक 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को मूल नागरिक माना गया है। इसके बाद के लोगों को अवैध नागरिकों की सूची में 329 किया गया है। इस सूची के अनुसार 1.29 करोड़ नागरिकों में से 2.89 करोड़ लोगों के पास नागरिकता के वैध दस्तावेज हैं। शेष रह गए 40 लाख लोग फिलहाल अवैध नागरिकों की श्रेणी में रखे जा रहे हैं। इस तरह के संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल घुसपैठिए अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो यह उन राजनीतिक दलों को वज्रद बचाए रखने की दृष्टि से खतरे की घंटी है, जो मुस्लिम तृष्टिकरण की राजनीति करते हुए



घुसपैठ को बढ़ावा देकर अवैध नागरिकता को वैधता देने के उपाय करते रहे हैं। असम में अवैध घुसपैठ का मामला नया नहीं है। 1951 से 1971 से की वीच राज्य में मतदाताओं की संख्या अचानक 51 प्रतिशत बढ़ गई। 1971 से 1991 के बीच यह संख्या बढ़कर 89 फीसदी हो गई। इस 2011 से 2011 के बीच मतदाताओं की तादात 53 प्रतिशत बढ़ी। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से यह भी देखने में आया कि असम में हिंदू आबादी तेजी से घटी है और मुस्लिम आबादी तेजी बढ़ी है। 2011 की जनगणना में मुस्लिमों की आबादी और तेजी से बढ़ी। 2001 में जहां यह बढ़ोत्तरी 30.9 प्रतिशत थी, वहीं 2011 में बढ़कर 34.2 प्रतिशत हो गई।

जबकि देश के अन्य हिस्सों में मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोत्तरी 13.4 प्रतिशत से 14.2 फीसदी तक ही हुई। असम में 35 प्रतिशत से अधिक मुस्लिमों वाली 2001 में विधानसभा संघिट 36 थी, जो 2011 में बढ़कर 39 हो गई। गौरतलब है कि 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद से 1991 तक हिंदुओं की जनसंख्या में 41.89 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या में 77.42 फीसदी की बेलगाम वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह 1991 से 2001 के बीच असम में हिंदुओं की जनसंख्या 14.95 प्रतिशत बढ़ी, जबकि मुस्लिमों की

स्थानीय आदिवासी और घुसपैठी मुसलमान हैं।

इन घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता देने के काम में असम राज्य कांग्रेस की राश्ट्र विरोधी भूमिका रही है। घुसपैठियों को अपना बंदूक बनाने के लिए कांग्रेसियों ने इन्हें बैंडी संख्या में मतदाताओं का हथियार पत्र एवं राशन कार्ड तक हासिल कराए। नागरिकता दिलाने की इसी पहल के चलते घुसपैठिए कांग्रेस को हलक के चलते अन्देखा करता रहा है।

झोली भर-भर के वोट देते रहे हैं। कांग्रेस की तरुण गोगाई सरकार इसी बूते 15 साल सत्ता में रही। लेकिन लगातार घुसपैठ ने कांग्रेस को हलत पतन कर दी थी। फलस्वरूप भाजपा सत्ता में आ गई। इस अवैध घुसपैठ के दुरप्रभाव पहले अलगाववाद के रूप में देखने में आ रहे थे, लेकिन बाद में राजनीति में प्रभावी हस्तक्षेप के रूप में बदल गए। इन दुरप्रभावो को पूर्व संसद्देख रहा कांग्रेस का केंद्रीय व प्रांतीय नेतृत्व जानबूझकर वोट बैंक बनाए रखने की दृष्टि से अनदेखा करता रहा है।

लिहाजा धुबरी जिले से सटी बांग्लादेश की जो 134 किलोमीटर लंबी सीमा-रेखा है उस पर कोई चौकसी नहीं है। नतीजतन घुसपैठ आसानी से जारी है। असम को बांग्लादेश से अलग ब्रह्मपुत्र नदी करती है। इस नदी का पाट इतना चौड़ा और दलदली है कि इस पर बताना लाया या दीवार बनाना नामुमकिन है। केवल नावों पर सशस्त्र

पहरेदारी के जरिए घुसपैठ को रोका जाता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सर्मा के घुसपैठियों के विरुद्ध कड़े रख के चलते इनकी वापसी भी पुरु हुई है।

दरअसल 1971 से ही एक सुनिर्गोजित योजना के तहत पूर्वांचल भारत, बंगाल, बिहार और दूसरे प्रांतों में घुसपैठ का सिलसिला जारी है। म्यांमार से आए 60,000 घुसपैठिए रोहिंगा मुस्लिम भी कश्मीर, बंगलुरु और हैदराबाद में गलत तरीकों से भारतीय नागरिक बनते जा रहे हैं।

जबकि कश्मीर से हिंदू, सिख और बौद्धों को धकिया कर पिछले 3 दशक से शरणार्थी बने रहने को विवश कर दिया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार ने तत्कालीन असम सरकार के साथ मिलकर फैसला लिया था कि 1971 तक जो बांग्लादेशी असम में घुसे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी और बाकी को भारत की जमीन से निर्वासित किया जाएगा। इस फैसले के तहत ही अब तक सात बार एनआरसी ने नागरिकों की वैध सूची जारी करने की कोशिश की, लेकिन हिंसक घुसपैठ के कारण ही नागरिकता के चलते कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल एनआरसी का विरोध करते रहे हैं।

बांग्लादेश के साथ भारत की कुल 4097 किलोमीटर लंबी सीमा-पट्टी है, जिस पर जरूरत के मुताबिक सुरक्षा के इंजाम नहीं हैं। इस कारण गर्बीओ और भुखमरी के मारे बांग्लादेशी असम में घुसे चले आते हैं।

## संक्षिप्त समाचार

## फंदे पर लटका मिला 25 साल की विवाहिता का शव, छह साल पहले हुई थी शादी

मेरठ, एजेंसी। लोहियानगर थाना क्षेत्र की अलीबाग कॉलोनी में रविवार शाम तैयबा (25) का शव घर में फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दिल्ली के जनापुर निवासी तैयबा की शादी करीब छह साल पहले सरताज से हुई थी। सरताज टैपो चलाता है। दोनों अलीबाग कॉलोनी में करीब एक साल से किराए के मकान में दो बेटीयां और एक बेटे के साथ रह रहे थे। रविवार शाम चार बजे तैयबा का शव घर में पंखे पर फंदे से लटका मिला। सूचना पर तैयबा के परिजन दिल्ली से आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए हत्या की है। पति सरताज शराब पीकर उसे आप दिव्य पीटा था। पुलिस ने शव मोर्चरी भिजवाया। सीओ कोतवाली अंतर्निष्ठा जैन का कहना है कि प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

## नई दरें लागू...गोरखपुर के फुटकर से लेकर थोक बाजार तक टूट्टेगी सुस्ती- बोले व्यापारी; सस्ते होंगे सामान



गोरखपुर, एजेंसी। जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। व्यापारियों ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि अब वस्तुएं कम कीमत पर बेची जाएंगी, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि जीएसटी दरों में अंतर से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। घोषणा के बाद से ही व्यापारी सावधानी बरतते हुए सीमित मात्रा में ही माल मंगा रहे थे। अब नई दरें लागू होने की तिथि आने के साथ ही उन्होंने प्रदेई आर्डर देना शुरू कर दिया है। शहर के थोक और खुदरा व्यापारियों का कहना है कि दरों में कटौती का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। इससे त्योहारी सीजन में बिक्री भी बढ़ेगी। व्यापारियों ने बताया कि सरकार की नीति उपभोक्ताओं व कारोबारियों दोनों के लिए लाभकारी है। जीएसटी दरों के कम होने से रोजमर्रा की जरूरतों के सामान सस्ते होंगे और खपत बढ़ेगी। वहीं व्यापारी भी ज्यादा बिक्री कर सकेंगे। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों ने डिस्काउंट ऑफर और नए स्टॉक की तैयारी कर ली है। नई दरों को लेकर लोगों में उतारूह है। उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार का यह फैसला घरेलू बजट को राहत देगा। वहीं व्यापारियों को भरपूर है कि बिक्री बढ़ने से उनका कारोबार और मजबूत होगा।

## आधी रात पुलिस से हुआ बदमाशों का सामना, पैर में गोली लगने से एक घायल; चोरी करने निकला था गंग

बहराइच, एजेंसी। यूपी के बहराइच में रविवार की रात हुजूरपुर-कैसरगंज बार्डर पर बदमाशों का सामना एसआजी और कैसरगंज थाना पुलिस से हो गया। रोकने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दी। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फरार बदमाशों की तलाश जारी है। सीओ कैसरगंज रवि खोखर ने बताया कि जिले में झोन उठने और चोरों के आने की अफवाह की वजह से एसआजी और पुलिस टीम रातभर क्षेत्रों में गश्त कर रही है। इसी बीच रविवार की आधी रात करीब 1-30 बजे सराय कनहर गांव की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ से कुछ लोग आते दिखे। टीम ने उनको आवाज देकर रुकने का इशारा किया। रुकने की बजाय उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में दो चक्र फायरिंग की। इसमें दहिने पैर में गोली लगने से बदमाश मुल्कराज पुत्र श्याम बिहारी, निवासी रायपुर, थाना बौडी, जखमी हो गया। मुल्कराज के पास से तमंचा और नाल में फंसा एक खोखा कारतूस, जब से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसे पहले सीएचसी ले जाया गया। वहां से मीडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस मुल्कराज में पकड़े गए बदमाश मुल्कराज ने बताया कि वह सभी मिलकर क्षेत्र में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए सराय कनहर गांव की तरफ जा रहे थे। उसने अपने साथियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। उनकी संख्या पांच के आसपास है। फरार साथियों की तलाश की जा रही है।

## काशी में 72 दिन बाद गंगा में होगा नौका संचालन इन शर्तों के साथ 11 घंटे चलेंगी नाव

वाराणसी, एजेंसी। काशी आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। 23 सितंबर से गंगा में नौका संचालन शुरू होगा। हालांकि सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ही नौका संचालन की अनुमति होगी। नाव की क्षमता के हिसाब से 50 प्रतिशत ही श्रद्धाकैंड बैठा सकेंगे। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 11 जुलाई से नाव संचालन पर प्रतिबंध है।

शाम 5.30 बजे तक घाट पर खड़ी हो जाएंगी सभी नावें : गंगा में नाव और मोटरबोट संचालन को लेकर रविवार को दशरथवमेध स्थित जल पुलिस परिसर में मांझी समाज के अध्यक्ष, मोटरबोट मालिकों व निषाद समाज के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। तय हुआ कि 23 सितंबर से मोटरबोट का संचालन होगा। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक नाव का संचालन निर्धारित है। शाम 5.30 बजे तक सभी नाव घाट पर खड़ी हो जाएंगी। तब तक मोटर बोट की सर्विसिंग, रंगरोमन आदि कार्य पूरा करा लें। यात्रियों के चढ़ने-उतरने वाले स्थान



की साफ-सफाई की जिम्मेदारी बोट मालिकों की होगी।

नाव को गंगा आरती में लगाने की अनुमति नहीं : एसीपी जल पुलिस शुभम सिंह ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी भी नाव को घाट पर गंगा आरती में लगाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश एक सप्ताह के लिए लागू रहेगा। इस्पेक्टर राजकिशोर पांडेय ने कहा कि सोमवार को अपनी नाव, मोटरबोट की मरम्मत समेत अन्य कार्य पूरा करा लें।

50 प्रतिशत यात्रियों को ही नाव में बैठाएं : जल पुलिस प्रभारी शशि प्रताप सिंह ने हिदायत दी कि निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत यात्रियों को ही नाव में बैठाकर बोटिंग कराएँ। सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य है। नशे की हालत में यदि किसी नाविक ने किसी भी यात्री को बैठाया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बैठक में मांझी समाज के प्रमोद मांझी आदि रहे।

## सीएम योगी बोले, जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता दें अधिकारी,

## 25 लोगों की सुनी समस्याएं

गोरखपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र को प्रतिपादित कर शक्ति की उपासना से पहले जनसेवा की। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात की। उनकी समस्याएं सुनीं और प्रभावी निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश दिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जनकृतमद व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया सुनिश्चित करें।

सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वासन दिया। हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी व संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा।

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनीं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही। इस दौरान एक महिला ने राशन कार्ड न होने की समस्या बताई। इस पर

मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला समस्या को संवेदनशीलता से देखें। राशन कार्ड की व्यवस्था करने के साथ पात्रता के अनुसार पेंशन योजना का भी लाभ दिलाएं।

जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गरीबों को जमीन पर कब्जा न होने देने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरपूर आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस्टीमेट की प्रक्रिया को प्राथमिकता पर पूर्ण करारण शासन को उपलब्ध कराएँ। शासन से इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

## शुक्लागंज बवाल: बिना अनुमति निकला जुलूस, खुफिया तंत्र फेल, पुलिस को दौड़ाया

कानपुर, एजेंसी। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र में रविवार देर शाम को मौहल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब आई लव मोहम्मद के समर्थन में बिना अनुमति के एक जुलूस निकला, लेकिन इसकी भनक पुलिस और खुफिया विभाग को नहीं लगी, जिससे काफी कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे काफी कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे काफी कार्रवाई नहीं हो पाई। इस दौरान, कोतवाली में तैनात एक इस्पेक्टर की वृद्धि से स्टार तक नोच लिए गए। हालात को बेकाबू होते देख, पुलिस को हल्का बल प्रयोग और आंशिक रूप से लाठीचार्ज करना पड़ा। जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और गंगाघाट, सदर कोतवाली, अचलगंज और बीघापुर से



बिगड़ गई और अक्रोशित लोगों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान, कोतवाली में तैनात एक इस्पेक्टर की वृद्धि से स्टार तक नोच लिए गए। हालात को बेकाबू होते देख, पुलिस को हल्का बल प्रयोग और आंशिक रूप से लाठीचार्ज करना पड़ा। जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और गंगाघाट, सदर कोतवाली, अचलगंज और बीघापुर से

अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसो बुलाई गई। पुलिस ने एहसासों को हिरासत में लिया है। छह लोगों उत्तरी अखिलेश सिंह ने बताया कि शहर में धारा 163 लागू है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात को नियंत्रित किया है। फिलहाल, क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

लाठीचार्ज के बाद, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और उन्हें मनोहर नगर से सीताराम कॉलोनी तक करीब 300

## वाराणसी शहर का हाल: तीन जगह आधी, दो जगह चौथाई बनाकर छोड़ी सड़कें,

## पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताई ये वजह

वाराणसी, एजेंसी। शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। तीन जगह आधी अधूरी तो दो स्थानों पर चौथाई सड़क बनाकर छोड़ दी गई है। इसकी चर्चा चलते चालकों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रवींद्रपुर में पंचश्री के पास, सिड्डीगिरीबाग, सिराना में आधी और मंडुवाडीबाग, सोनिया पर चौथाई सड़क बनाकर छोड़ी गई है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह पुलिस लाइन से ताज होटल, लहरतारा से रविदास घाट तक सड़क की मरम्मत कराई गई है। इसके निर्माण भी अधूरे हैं।

नदेसर पर धर्म सड़क, पीडब्ल्यूडी ने भरवाया गड्ढा : नदेसर पर इमलाक कॉलोनी के समीप सड़क पर एक तरफ सड़क धंस गई है। इसके चारों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग कराई ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए। इसी सड़क से आठ दिन वीआईपी गुजरते हैं।



खोदाई के अधिकारी ने बताया कि शहर की सड़कों को अनुमति के बाद ही खोदने का नियम है। काम कराने के बहाने मनमाने तरीके से सड़कों की खोदाई का सिलसिला जारी है। ऐसे में धूल और कीचड़ से सनी खस्ताहाल सड़कों पर फिर से मरम्मत का लेपन किया जा रहा है। कई एजेंसियों की ओर से मुख्य मार्गों, कॉलोनीयों की सड़कों और गलियों तक को खोद कर छोड़ दिया गया था जिसकी पैचिंग देर से कराई गई।

पाइप लाइन बिछाने के लिए नदेसर, सिराना, रथयात्रा,

तेलियाबाग और फातमान रोड सहित कई इलाकों में काम कराया जा रहा है। भूमिगत बिजली की केबिल बिछाने के लिए कैट से भेलपुर, लहराबीर से मैदानिया, नई सड़क, लक्सा, लंका, सुंदरपुर-डेरिका समेत कई प्रमुख मार्ग और गलियों को खोद दिया गया।

वहीं, पेजयल और सीवेज पाइप लाइन बिछाने के लिए जल निगम की ओर से पहडिया-बेला मार्ग और चौकाघाट सहित कई इलाकों में काम कराया जा रहा है। अभी तक खोदे गए गड्ढों को पाटकर सड़क बनाने का काम नहीं शुरू किया गया है।

## आकांक्षा ने जिस सूटकेस पर बैठ बनवाई रील उसी में भरकर प्रेमी ने फेंका शव

फतेहपुर, एजेंसी। प्रेम संबंध में जान गंवाने वाली आकांक्षा ने जिस सूटकेस पर बैठकर रील बनवाई थी उसी सूटकेस में उसका शव भरकर प्रेमी सूरज ने यमुना में फेंक दिया। फिलहाल सूरज जेल में है और पुलिस आकांक्षा को तलाशने के लिए यमुना नदी में सर्च अभियान चला रही है।

थानाध्यक्ष हनुमंत विहार राजीव सिंह ने बताया कि कानपुर देहात के सुजनपुर गांव निवासी विजय श्री की बेटी आकांक्षा के शव को पुलिस टीम बांदा, चित्रकूट,

फतेहपुर आदि में तलाश कर रही है। साथ ही इन जनपदों में बीते दिनों यमुना में मिले अज्ञात महिलाओं के शवों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही प्रयागराज से यमुना के गंगा में मिल जाने के कारण वहां के थानाक्षेत्रों से भी संपर्क किया गया है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि शांतिर सूरज कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाए था।

इसकी जानकारी जब आकांक्षा को हुई तो उसने विरोध किया। पहले तो उसने

दोबारा ऐसा न करने का भरपूर दिलाया लेकिन लड़कियों से बात करना बंद नहीं किया। 21 जुलाई की शाम को भी इन दोनों में रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ। इसके बाद सूरज उत्तम ने उसकी हत्या कर दी।

## यह थी घटना

20 साल की आकांक्षा बड़ी बहन के साथ बर्रा में रहती थी। फतेहपुर के बिंदकी के हरीखेड़ा निवासी सूरज उत्तम से उसके इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रेम संबंध हो गए। सूरज के कने पर वहां से नौकरी छोड़कर हनुमंत विहार के रेस्टोरेंट में काम करने लगी। वहीं सूरज ने कमरा भी दिला दिया। उसी कमरे में 21 जुलाई की रात गला दबाकर हत्या करने के बाद शव सूटकेस में भरकर साथी आशीष संग बाइक से चिल्ला घाट से नीचे यमुना में फेंक दिया।

## आशीष ने दी थी शव को यमुना में फेंकने की सलाह

पुलिस को पृच्छाछ में सामने आया है कि हत्या करने के बाद सूरज ने दोस्त आशीष को फोन कर घर बुलाया था जहां पहुंचकर शव देखने के बाद उसने कहा था कि इस समय यमुना में बाढ़ चल रही है। यहीं से लेकर शव को बांदा चलो वहीं चिल्ला घाट से नदी में फेंक देंगे किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बाद सूरज ने शव को बैग में भरकर बाइक पर रखा जबकि बाइक आशीष ने चलाई। इसके बाद दोनों लोग बाइक में बैग रखकर चिल्लाघाट पहुंचे और शव को यमुना में फेंक दिया।

## एमपी सरकार काशी में कराएगी इन्वेस्टर्स मीट, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम



वाराणसी, एजेंसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नवंबर में वाराणसी में इन्वेस्टर्स मीट कराने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस सिलसिले में रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल रीवा में सीएम मोहन यादव से मिला है।

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों के साथ अलग-अलग वार्ता कर निवेश के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी आवश्यकता के लिए जिला कलेक्टर, औद्योगिक विकास

आयुक्त मध्य प्रदेश एवं मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे संपर्क में रहने की बात कही। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने हनुमाना के पास स्थित औद्योगिक क्षेत्र को देखा।

इस दौरान मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निदेशक रीवा संभाग यूके तिवारी व पूरी टीम उपस्थित रही। प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएस मिश्रा, महामंत्री राकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष सुरेश पटेल, उपाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, प्रतिष्ठित उद्यमी प्रमोद चौसिया, जिसके बाद अदालत से उन्हें रिमांड पर देने का अनुरोध किया जाएगा।

## लापरवाही में ठाकुरद्वारा सीओ-थाना प्रभारी हटाए

मुरादाबाद, एजेंसी। एसएसपी सतपाल अंतिल ने जिले के तीन सीओ और तीन इस्पेक्टरों को इधर से उधर किया है। आरोप है कि ठाकुरद्वारा सीओ और थाना प्रभारी लापरवाही के आरोप में हटाए गए हैं। एसएसपी सतपाल अंतिल ने रविवार को सभी के आधार पर सीओ ठाकुरद्वारा गौरव कुमार त्रिपाठी को सीओ कार्यालय/जनशिकायत/यूपी-112 और सीओ यातायात की जिम्मेदारी सौंपी है।

ठाकुरद्वारा सिक्के में सीओ काठ आशीष प्रताप सिंह को तैनाती दी गई है। सीओ राजेश कुमार तिवारी को सीओ मुख्यालय और न्यायालय संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह थाना प्रभारी ठाकुरद्वारा जसपाल सिंह ग्याल को वहां से हटाकर कुंदरकी का थाना प्रभारी बनाया गया है।

इसी प्रकार थाना प्रभारी छल्लैट संजय पांचाल को ठाकुरद्वारा थाने की जिम्मेदारी दी गई है। थाना प्रभारी कुंदरकी प्रदीप कुमार सहरावत को छल्लैट का थाना प्रभारी बनाया गया है।

इस बारे में एसएसपी ने बताया कि समीक्षा के दौरान सीओ ठाकुरद्वारा की लापरवाही प्रकाश में आई थी लेकिन



यह मामला गोकशी वाले सपा नेता से नहीं जुड़ा है। अन्य मामलों में लापरवाही प्रकाश में आई थी। तीनों थाना प्रभारियों को सामयोजित किया गया है।

गोकशी के मामले में पुलिस की कार्रवाई से साधु संतुष्ट नहीं : ठाकुरद्वारा के शिवनगर पथर खेड़ा

में 25 जुलाई को हुए गोकशी के मामले की कार्रवाई से साधु-संत और हिंदू संगठन संतुष्ट नहीं है। इस मामले में प्रमुख रूप से सक्रिय शिवनगर मंदिर के महंत बच्चा बाबा ने बताया कि साधु संतों और हिंदू संगठनों की एक बैठक हुई है। जिसमें पुलिस की इस मामले में की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई। जिसमें उपस्थित लोगों ने कहा कि पुलिस ने गोकशी के मामले में की गई कार्रवाई में लापरवाही की है। 25 जुलाई को सुबह 9-35 पर घटना का दिखलाया गया है जबकि यह घटना सुबह लगभग 4-00 बजे की थी।

जिसके सबूत उनके पास है। इसमें एक आरोपी ने अपने बचाव ले लिए अपनी लोकेशन 9-30 बजे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई है। पुलिस की लापरवाही के चलते इस मामले के कई आरोपियों को कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है।

बच्चा बाबा ने कहा कि शीघ्र एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस प्रशासन के स्थानीय और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेगा। उन्हें अपने असंतोष को अवगत कराएगा। यदि कोई कार्रवाई नहीं हो तो इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ले जाया जाएगा।

## फिलीस्तीन के लिए फ्राउड फंडिंग की रकम हड़पने वाले तीन युवक महाराष्ट्र से गिरफ्तार, एटीएस की कार्रवाई

लखनऊ, एजेंसी। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के ठाणे और भिवंडी से तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। ये फिलीस्तीन के गाजा में युद्ध पीड़ितों की मदद के नाम पर क्राउड फंडिंग करने के बाद करोड़ों रुपये हड़प चुके हैं। तीनों के संपर्क में यूपी के कई जिलों के लोग भी थे, जो क्राउड फंडिंग में मदद कर रहे थे। तीनों के पास से तीन मोबाइल बरामद किए गए हैं। एटीएस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लेकर आ रही है।

एडीओ कानून-व्यवस्था अमिताभ भय ने बताया कि एटीएस को खुफिया सूचना मिली थी कि गाजा में युद्ध पीड़ित महिलाओं, बच्चों के लिए खाना, पानी, कपड़ा, दवाएं आदि के नाम पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आर्थिक मदद मांगी जा रही है। उन्होंने यूपी समेत देश भर से गाजा युद्ध पीड़ितों की मदद के लिए करोड़ों रुपये जमा किए हैं। बाद में इस रकम को गाजा न भेजकर हड़प ली। इस सूचना पर एटीएस ने बीते अगस्त माह में भिवंडी

निवासी मोहम्मद अयान, अबू सूफियान और ठाणे निवासी जैद नोटियार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। अदालत से तीनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट लेकर ठाणे से पीछड़ा इलाके से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों से फंडिंग में पता चला कि वह सोशल मीडिया पर गाजा युद्ध पीड़ितों के लिए मार्फिक पोस्ट करते थे।

सोशल मीडिया कैम्पेन में तीनों ने अपनी यूपीआई आईडी और बैंक खातों का इस्तेमाल किया, जिसमें यूपी के कई जिलों समेत देश भर से करोड़ों रुपये चंदा आया। एटीएस तीनों को रिमांड पर लेकर पता लगाएगी कि इस रकम को इस्तेमाल कहीं टेरर फंडिंग के लिए तो नहीं किया है। तीनों को सोमवार को राजधानी स्थित एटीएस/एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद अदालत से उन्हें रिमांड पर देने का अनुरोध किया जाएगा।

